राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1698/2011/भरतपुर.
2. अपील संख्या – 1699/2011/भरतपुर.

सहायक आयुक्त, वृत्त–ए, भरतपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स कुमार सिलिका सेन्ट सप्लायर्स,
विलंग तहसील कांमा. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. के. बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री श्री ओ. पी. गुप्ता, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 13/10/2016

निर्णय

1. यह दोनों अपीलें अपीलार्थी सहायक आयुक्त, वृत्त–ए, भरतपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 44 व 45/उपा–अपील्स/2010–11 आदेश दिनांक 09.12.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 09.12.2010 के द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 30 सपठित धारा 9 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे **'केन्द्रीय अधिनियम'** कहा जायेगा) के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 2003–04 व 2004–05 के लिये पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.03.2010 के द्वारा आरोपित कर राशि क्रमशः रूपये 8,35,314/– व रूपये 8,84,888/– के सम्बन्ध में करारोपण को यथावत रखते हुए अपीलें स्वीकार की गई है। अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलें स्वीकार करने को विवादित किया है। दोनों अपीलों का निस्तारण समान तथ्य होने के कारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। आदेश की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का कर निर्धारण वर्ष 2003–04 का नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 16.03.2006 को प्रस्तुत बिक्री विवरण पत्रों के आधार पर घोषित बिक्री रूपये 2,40,64,500/– व कर निर्धारण वर्ष 2004–05 के लिये घोषित बिक्री रूपये 2,15,46,000/– के आधार पर पारित किया गया। इसके पश्चात प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 37 के तहत रिफण्ड हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर यह पाये जाने पर कि प्रत्यर्थी

लगातार.....2

व्यवहारी ने विक्रय मूल्य कम प्रदर्शित किया है, पर्य्यावर्त बढ़ जाने के कारण अतिरिक्त करारोपण किया। कर निर्धारण वर्ष 2003—04 में सकल बिक्री रूपये 2,40,64,500/— से बढ़ाकर रूपये 3,01,17,500/— की गई तथा कर निर्धारण वर्ष 2004—05 में सकल बिक्री रूपये 2,15,46,000/— से बढ़ाकर रूपये 3,16,35,300/— की गई तथा पूर्व में जमा कराई गई कर राशि को समायोजित किया गया तथा रिफण्ड कुछ भी देय नहीं होना निर्धारित किया गया।

3. अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस में कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करने में त्रुटि कारित की है। अपीलीय अधिकारी का आदेश अविधिक एवं तथ्यों के विपरीत है। अपीलीय अधिकारी के आदेश के कारण प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा स्वैच्छा से जमा कराये गये कर का गलत रिफण्ड जारी किया गया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बाजार दर से कम दर पर बिक्री मूल्य घोषित करने के कारण सकल बिक्री घटा कर घोषित की गई थी। प्रत्यर्थी व्यवहारी आलौच्य अवधि के दौरान विभिन्न चैकपोस्टों पर वर्ष भर नियमित कर का भुगतान करता आ रहा था। आलौच्य अवधियों के दौरान अण्डर बिलिंग के कारण कर निर्धारण को खोलते हुए सही कर निर्धारण आदेश पारित किये गये। विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करने की मांग करते हुए अपीलें स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को उचित बताया। बहस के दौरान अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये :—

A. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन—प्रथम, वृत्त—द्वितीय, जयपुर बनाम मैसर्स पायोटेक लाईटिंग एण्ड स्वीचगियर्स, जयपुर, अपील संख्या 391/2001/जयपुर निर्णय दिनांक 16.12.2002 न्यायिक दृष्टान्त 5 टैक्स अपडेट 43

B. मैसर्स बी.एल.करनानी, 5—सी, सादुलगंज बीकानेर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, बीकानेर अपील संख्या 135, 136/2002/बीकानेर निर्णय दिनांक 29.10.2002 न्यायिक दृष्टान्त 5 टैक्स अपडेट 37

C. वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन कोटा, बनाम मैसर्स आनंद मिनरल्स प्रा. लि., कोटा अपील संख्या 1068/1999 एवं 778, 779/2001/कोटा निर्णय दिनांक 31.10.2001 न्यायिक दृष्टान्त 4 टैक्स अपडेट 7

लगातार.....3

D. वाणिज्यिक कर अधिकारी विशेष वृत्त—उदयपुर बनाम फ्रेगरेन्स कॉस्मेटिक्स प्रा. लि., एस.टी.आर. नं. 162 व 171/2007 निर्णय दिनांक 17.11.2008 न्यायिक दृष्टान्त 25 टैक्स अपडेट 6

बहस के अन्त में विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी राजस्व की अपीलें अस्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

5. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया व पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2003—04 व 2004—05 की अवधि में अपने द्वारा बेचे जाने वाले माल पर चैकपोस्टों पर कर जमा कराया गया था। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने कर निर्धारण वर्ष 2003—04 व 2004—05 में बिक्री विवरण प्रपत्रों में जो बिक्री राशि घोषित की उसके आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश पारित कर दिये। इसके पश्चात प्रत्यर्थी व्यवहारी ने संशोधन प्रार्थना पत्र के माध्यम से रिफण्ड की मांग की। कर निर्धारण अधिकारी ने बिक्री विवरण पत्रों में बिक्री राशि कम घोषित करने की अवधारणा के आधार पर निर्धारित की गई कर राशि को बढ़ाते हुए उसका समायोजन किया गया।

6. अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में यह लिखा है कि व्यवसायी के अधिकृत प्रतिनिधि का यह कथन की सिलिका सेन्ट केज्युअल कमोडिटि नहीं है एवं इस पर वजन के आधार पर चैकपोस्ट पर कर नहीं काटा जाना था, उचित है। व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत बिलों व चैक पोस्टों की रसीद के मिलान करने पर यह पाया गया कि बिलों में कर कम चार्ज किया गया है जबकि चैकपोस्ट रसीद में वजन के आधार पर अधिक कर वसूल किया गया है। इस प्रकार का कोई आदेश या जाँच चैकपोस्ट इन्चार्ज द्वारा नहीं की गई है, केवल अपनी मर्जी से ही कर वसूल किया गया है। माननीय राजस्थान टैक्स बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त **4 टी.यू.डी. 312 वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन बनाम आनंद मिनरल्स** में भी यह प्रतिपादित किया है कि कर निर्धारण अधिकारी को उचन्ती बिक्री को साबित करने हेतु निष्पक्ष जाँच करनी चाहिए थी जो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं की गई है। अपीलीय अधिकारी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **4 टी.यू.डी. 312** का अवलम्बन लिया है जो हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से कोई मेल नहीं खाता है, क्योंकि न्यायिक दृष्टान्त **4 टी.यू.डी. 312** में यह निर्णीत किया गया कि **'आयकर विभाग द्वारा निर्धारित आय को बिक्री कर आरोपित करने के लिये आधार नहीं बनाया जा सकता है उसके लिये स्वतंत्र जांच आवश्यक है ताकि यह निश्चय किया जा सके कि कर योग्य माल की बिक्री से कितनी आय प्राप्त हुई है।'** अपीलीय अधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण निर्वचन किया गया है।

लगातार.....4

7. अधिनियम की धारा 25, 26, 29, 30 व 56 का अध्ययन प्रासंगिक है, जो निम्न प्रकार है :—

Section 25. Payment of tax

(1) Tax payable under this Act shall be deposited into a government treasury or a bank authorised to receive money on behalf of the State Government on the basis of the accounts of a dealer in such manner and at such intervals as may be prescribed for different categories of dealers.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government may by notification in the Official Gazette require any dealer or class of dealers specified therein, to pay tax at intervals shorter than those prescribed under sub-section (1).

(3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest so to do, it may, by notification in the Official Gazette, defer the payment of tax payable by any class of dealers, with or without interest, for any period on such conditions and under such circumstances as may be specified in the notification.

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, in the case of a works contract, an amount in lieu of tax may be deducted by the awarder at such rate not exceeding three per cent of the total value of the contract, in such manner and under such circumstances as may be prescribed, from every bill of payment to a contractor and such sum shall be deposited or credited in the government account within the specified time and in the prescribed manner.

(5) Every deposit of tax or deduction of amount in lieu of tax made under this section shall be deemed to be provisional subject to adjustment against the tax liability determined in the assessment for any year made under section 29.

Section 26. Filing of returns

(1) Every registered dealer, and such other dealer as may be required by notice to do so by the assessing authority shall furnish prescribed returns, for the prescribed period, in the prescribed form, in the prescribed manner and within the prescribed time to the assessing authority.

लगातार.....5

(2) The assessing authority may extend the date for submission of any return to be filed by any dealer or class of dealers under sub-section (1) by a period not exceeding fifteen days.

(3) Every return to be filed under sub-section (1) shall be accompanied by a treasury receipt or receipt of the bank authorised to receive money on behalf of the State Government showing the deposit of full amount of tax due on the basis of the return.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no return shall be required to be filed by a registered dealer who deals in generally exempted and/or tax paid goods and whose turnover in the previous year does not exceed such limit as may be prescribed with or without any condition.

(5) Where a dealer discovers any omission or error in any return furnished by him under sub-section (1), he may furnish a revised return within [such time as may be prescribed not exceeding three hundred sixty five days] after the close of the year to which it relates, and the burden of proving that the omission or the error was *bona fide*, shall be on such dealer.

Section 29. Assessment

(1) Assessment for a year shall be made after the returns of that year have become clue, but a closed firm could be assessed immediately after its closure.

(2) In the case of a dealer whose turnover as determined in the last assessment order passed subsequent to the first assessment after his registration, does not exceed such limit as may be notified by the State Government in the Official Gazette in this behalf, the assessment of such dealer shall be made for two years at a time by one single order, after all the returns in respect of such period of two years have become due.

(3) In the case of works contract, the assessment of a contractor shall be made on the basis of the work done in a year and the amount paid or deducted at source in that year, if any, in lieu of tax, and in the case of a contractor opting for payment of exemption fee in lieu of tax, on the basis of amount of exemption fee paid or deducted at source in a year, and such year shall be deemed to be his accounting year.

(4) Where the assessing authority, on scrutiny is satisfied that the returns furnished by a dealer are correct and complete, it shall assess the tax on the basis of such returns.

लगातार.....6

(5) Where the assessing authority is not satisfied without requiring the presence of the dealer who has filed the returns or without production of accounts, registers and document including any other evidence, that the returns are complete and correct, it shall serve on such dealer a notice requiring him on a date and place to be specified there in -

(a) to appear in person, or by an agent duly authorised in writing; or

(b) to produce or cause to be produced such accounts, registers and documents as the assessing authority may require, or

(c) to produce or cause to be produced any evidence on which he may rely in support of the returns filed or the statements made, to the assessing authority.

(6) The assessing authority, after having examined the accounts, registers and documents produced or other evidence adduced before it and after issuing notice on specific points wherever necessary, shall, on the day specified in the notice issued under sub-section (5), or as soon as possible thereafter, assess the tax by an order in writing.

(7) The assessing authority after affording an opportunity of being heard, shall assess a dealer to the best of its judgment and determine the tax payable by him, if such dealer -

(a) has not filed all or any of the returns due for a year; or

(b) has filed any return or returns which appear to the assessing authority incomplete or incorrect; or

(c) has failed to comply with all the terms of a notice issued under sub-section (5); or

(d) has not regularly employed any method of accounting, or if the method employed is such that in the opinion of the assessing authority, assessment cannot properly be made on the basis thereof; or

(e) has with a view to avoid or evade tax, shown in this accounts, registers or documents, sale or purchase of any goods at a price which is lower than the prevailing market price of such goods; or

(f) has concealed any transaction of purchase or sale from his accounts, registers or documents or has avoided or evaded tax in any other manner.

लगातार.....7

(8) (a) No assessment order under this section shall be passed after the expiry of two years from the end of the relevant assessment year or one year after coming into force of this Act, whichever is later; however, the Commissioner may for reasons to be recorded in particular case may extend such time limit by a period not exceeding six months.

(b) Notwithstanding anything contained in sub-clause (a), where an assessment order is passed in consequence of or to give effect to, any order of an appellate authority or the tax board or a competent court, it shall be completed within two years of the communication of such order to the assessing authority; however, the Commissioner may for reasons to be recorded in writing, extend in any particular case, such time limit by a period not exceeding six months.

Section 30. Escaped assessment

(1) An assessment -

(a) of a person who is liable to get registration but has not got himself registered; or

(b) in which, for any reason, the levy of tax or any fee or sum payable under the Act has been escaped wholly or in part; or

(c) wherein tax has been wholly or in part unassessed or under-assessed in any way and under any circumstances,

shall be deemed an escaped assessment and the assessing authority shall on the basis of the material on record or after making such enquiry as it may consider necessary, complete such assessment within the limit provided in sub-section (3).

Explanation : The assessment under this section shall not include that part of business which has already been assessed under section 29.

(2) Where the Commissioner or a Deputy Commissioner (Administration) has reason to believe that a dealer has escaped assessment to tax in any manner provided in sub-section (1), he may at any time, subject to the time limit specified in sub-section (3), either direct the assessing authority to assess the tax or the fee or other sum or himself proceed to assess the same.

(3) No notice under sub-sections (1) and (2) shall be issued in respect of any escaped assessment for any year after the expiry of five years and no assessment under the said sub-section shall be completed after the expiry of eight years, from the end of the relevant assessment year, bur this limitation shall not be applicable to any assessment to be made in consequence of, or to

लगातार.....8

give effect to, any finding or direction contained in an order passed by an appellate authority or the Tax board or a competent court.

Section 56. Refund

(1) Where any amount is refundable to a dealer under the provisions of this Act, after having duly verified the fact of deposit of such amount, the assessing authority shall in the prescribed manner refund to such dealer the amount to be refunded either by cash payment or by adjustment against the tax or other sum due in respect of any other period and such refundable amount shall carry interest at the rate of fifteen percent per annum with effect from the date of its deposit.

(2) Where an amount or tax is collected at any checkpost from any person who is not registered under the Act and such amount or tax is not found payable by him, or where an amount in lieu of tax for any work is deducted in any manner by an awarder from any bill of payment to a contractor, who is not liable to get registration under the Act, the amount so collected or deducted shall be refunded in the prescribed manner by the Assistant Commissioner or the Commercial Taxes Officer, as the case may be, in whose territorial jurisdiction such person or contractor ordinarily resides; and where such person or contractor does not reside in the State, then such refund shall be made by such officer who may be directed by the Commissioner.

(3) Any tax levied and collected under this Act, in respect of the sale or purchase inside the State of any declared goods which are subsequently sold in the course of inter-State trade or commerce and on which tax has been paid under the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act 74 of 1956), shall be refunded to the person making such sale or purchase in the course of inter-State trade or commerce, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

(4) Notwithstanding anything contained in this section or in any other law for the time being in force, a refund can be claimed only by the dealer or the person, who has actually suffered the incidence of tax and the burden of proving the incidence of tax so suffered shall be on the dealer or the person claiming the refund.

8. अधिनियम की धारा 30 के सम्बन्ध में माननीय न्यायालयों के निम्न न्यायिक दृष्टान्तों में व्यवस्था दी गयी है कि –

लगातार.....9

(1) ए.आई.आर. 1959 एस.सी. 1303 महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह, उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय ने बिहार कृषि आयकर अधिनियम की धारा 26, जो कि राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 12 के समान है, के सम्बन्ध में निर्णय दिया है कि –

"Held that the expression 'any reason' used in the Act, is of wide import and dispenses with those conditions by which section 34 of the Income Tax Act in circumscribed."

(2) 1976 आर.एल.डब्ल्यू. 648 (राज.) मैसर्स अकबरअली अमानतअली

"Held that the words "for any reason" in section 12(1) or the Rajasthan Sales TAx Act, 1954 are wide enough and the powers of the Commercial Taxes Officer under the section are not circumscribed by any condition. The decision of the Division Bench in M/s National Clinic's case (1966 RLW 257) Which lays down that there can be no reassessment under section 12(1) of the Act on mere change of opinion, therefore, does not lay down good law."

(3) (1980) 45 एस.टी.सी. 274 (राज.) राजस्थान फेल्ट्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी

(4) (1983) 54 एस.टी.सी. 284 (राज.) कोटा बॉक्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी

"Held that the words "for any reason" in section 12(1) or the Rajasthan Sales Tax Act, 1954 are wide and the powers of the Commercial Taxes Officer reopen an assessment under the section are not circumscribed by any condition.

(5) (1986) 61 एस.टी.सी. 1 (मद्रास) डिनोद कैश्यू कॉर्पोरेशन

(6) (1977) 40 एस.टी.सी. 531 (मद्रास) येरकंड कॉफी क्योरिंग वर्क्स लिमिटेड

"Held that having regard to the use of words "for any reason" it was clear that even where a turnover was disclosed but it was not subjected to tax, because at the relevant time the assessing authority through that the particulars turnover was exempt from tax, it would be permissible for the assessing authority to reopen the assessment under section 16(1)(a) or the Tamil Nadu General Sales Tax, 1959."

(7) (1989) 75 एस.टी.सी. 13 (कर्नाटक) केशोराम रायन

"Held that section 12A of the Karnataka Sales Tax Act, 1957 conferred power on the assessing authority to make a reassessment even in cases where the entire turnover was before the assessing authority, but it had committed mistake in the matter of rate of tax in which a lower rate of tax than the one at which the tax ought to have been levied, had been levied."

लगातार.....10

(8) (1993) 90 एस.टी.सी. 25 (केरल) टी.पी. एलियास

(9) (1996) 103 एस.टी.सी. 55 (केरल) सी वी की एण्ड कम्पनी

"Held that section 19 of the Kerala General Sales Tax Act, 1963 enables the assessing authority to reopen an assessment to bring to tax turnover which had escaped assessment, whatever be the reason for the turnover having escaped assessment. A mere change of opoinion on the same material will be sufficient to reopen the assessment."

(10) एस.बी. सिविल रिट पिटिशन नं0 3675/2001 मैसर्स जील वुलन्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड ब्रदर्स (राज.)

"Held that the expression "in any way or under any circumstances", used in section 30 of the Rajasthan Sales Tax Act, 1994, are the expressions which have a very wider connotation. "In any way and under any circumstances" would give all permissible powers to the assessing authority. In that case the earlier assessment found to have faulted on the touch stone of the existing law, under-assessment is patiently there. Therefore, also the notice for reassessment cannot be said to be bad in the eye of law."

9. माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी कारण/हेतु से नियमित कर निर्धारण में किसी वस्तु पर करारोपण होने से रह जाने की स्थिति में, व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त प्रकरण को पुनः खोलते हुए छूटे हुए करारोपण की कार्यवाही की जा सकती है।

10. हस्तगत प्रकरण में विशेष उल्लेखनीय है कि नियमित रूप से बेचे गये माल पर देय कर को चैकपोस्टों पर जमा कराया है। जारी बिलों में यह कर क्रेता से वसूल किया जाता है। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में इस बिन्दु पर कोई विश्लेषण नहीं किया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को रिफण्ड क्यों देय होगा ? विक्रय बिलों में कर हमेशा कीमत का भाग होता है जो क्रेता द्वारा चुकाया जाता है। रिफण्ड के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्णयों में दी गई व्यवस्था निम्न प्रकार है :—

A. (1998) 111 एसटीसी 467 माफतलाल इण्डस्ट्रीज बनाम भारत सरकार (उच्चतम न्यायालय)

लगातार.....11

"The Concept of economic justice demands that in the case of indirect Taxes, the Tax collected without the authority of law shall not be refunded to the petitioner-plaintiff unless he alleges and establishes that he has not passed on the burden of tax to a third party and that he has himself borne the burden of the said tax."

B. (1994) 95 एस.टी.सी. 5 एन्ट्री टैक्स ऑफिसर बनाम चन्दनमल चम्पालाल एण्ड कम्पनी (उच्चतम न्यायालय)

"The normal presumption is that the dealer has passed on the incidence of tax to the purchaser/consumer. If he says otherwise, it is for him to allege and establish the same. In the absence of any such allegation and proof, the direction of refund is not called for."

11. प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का ससम्मान अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से भिन्नता के कारण ये प्रत्यर्थी व्यवहारी को कोई मदद प्रदान नहीं करते है।

12. अधिनियम की धारा 56(4) ऐसे मामलों में रिफण्ड देने को निषिद्ध करती है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा इन दोनों प्रकरणों में कर अधिक क्यों जमा कराया है इसका कहीं कोई कारण नहीं दिया है। कथित अधिक जमा कराया गया कर का भाग प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वहन किया गया है, इस बिन्दु पर भी प्रत्यर्थी व्यवहारी ने सबूत के भार का निर्वहन नहीं किया हैं।

13. उपरोक्त विस्तृत तथ्यात्मक एवं विधिक विश्लेषण के पश्चात यह निष्कर्षित किया जाता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 30 में पारित आदेश पूर्णतः विधिसम्मत है। अपीलीय अधिकारी का आदेश पूर्णतः त्रुटिपूर्ण एवं अविधिक है। अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती हैं तथा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते हैं कि वे कर के जमा होने का सत्यापन करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत आदेश पुनः पारित करें। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि क्रेतागण द्वारा कर का भार वहन किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी व्यवहारी को रिफण्ड देय नहीं होगा।

14. निर्णय सुनाया गया।

13/10/2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य